



RACE IAS

A Leading Institute For Civil Services Examinations

ANSWERS & EXPLANATIONS

GENERAL STUDIES (P) 2026

TEST 04 : INDIAN ECONOMY

EXAM DATE : 27-06-2026

QUESTIONS BOOKLET NO. : 6145602604

1. Answer: (b)

Explanation: National Income includes only the value of productive factor services rendered during the current accounting year. Brokerage earned on the sale of second-hand goods is payment for a current service and is therefore included. Transfer payments, lottery winnings, and illegal incomes are excluded as they do not arise from current legal production.

2. Answer: (c)

Explanation: WPI tracks changes in the prices of goods at the wholesale stage and does not cover services. CPI measures retail inflation faced by consumers and includes both goods and services. CPI (Rural, Urban and Combined) is released monthly by the NSO.

3. Answer: (d)

Explanation: An increase in SLR requires banks to maintain a larger proportion of their deposits in approved securities, reducing their lendable resources. This contracts credit availability and helps control inflation. The other measures would generally increase liquidity in the economy.

4. Answer: (c)

Explanation: Capital Receipts either create liabilities or reduce assets of the government. Disinvestment proceeds reduce the government's ownership of assets and are therefore classified as Capital Receipts. Taxes, dividends and grants are Revenue Receipts.

5. Answer: (b)

Explanation: NITI Aayog, established on 1 January 2015 as the successor to the Planning Commission, functions as the Government of India's premier policy think tank. The Prime Minister serves as its ex-officio Chairperson.

6. Answer: (b)

Explanation: The Capital Account records transactions that result in changes in the assets or liabilities of a country. FDI inflows involve foreign ownership of domestic assets and are therefore recorded under the Capital Account. Trade, remittances and interest payments are recorded in the Current Account.

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations



RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations



1. उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय आय में केवल मौजूदा अकाउंटिंग वर्ष के दौरान दी गई उत्पादक फैक्टर सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। सेकंड-हैंड सामान की बिक्री पर कमाई गई ब्रोकरेज एक मौजूदा सेवा के लिए भुगतान है और इसलिए इसे शामिल किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट, लॉटरी से हुई कमाई और अवैध आय को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे मौजूदा कानूनी उत्पादन से उत्पन्न नहीं होते हैं।

2. उत्तर: (c)

व्याख्या: WPI थोक स्तर पर सामान की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है और इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। CPI उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली खुदरा महंगाई को मापता है और इसमें सामान और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। CPI (ग्रामीण, शहरी और कंबाईड) को NSO द्वारा हर महीने जारी किया जाता है।

3. उत्तर: (d)

व्याख्या: SLR में वृद्धि से बैंकों को अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा स्वीकृत प्रतिभूतियों में बनाए रखना पड़ता है, जिससे उनके उधार देने योग्य संसाधन कम हो जाते हैं। इससे क्रेडिट की उपलब्धता कम होती है और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अन्य उपाय आम तौर पर अर्थव्यवस्था में तरलता (liquidity) को बढ़ाएंगे।

4. उत्तर: (c)

व्याख्या: कैपिटल रिसीट्स (पूंजीगत प्राप्तियां) या तो सरकार पर देनदारियां बढ़ाती हैं या उसकी संपत्ति कम करती हैं। डिसइन्वेस्टमेंट से मिली रकम सरकार की संपत्ति पर मालिकाना हक कम करती है, इसलिए इसे कैपिटल रिसीट्स माना जाता है। टैक्स, डिविडेंड और ग्रांट रेवेन्यू रिसीट्स (राजस्व प्राप्तियां) होती हैं।

5. उत्तर: (b)

व्याख्या: 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जो भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में काम करता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।

6. उत्तर: (b)

व्याख्या: पूंजी खाता उन लेन-देनों को दर्ज करता है जिनसे किसी देश की संपत्ति या देनदारियों में बदलाव होता है। FDI के आगमन में घरेलू संपत्तियों का विदेशी स्वामित्व शामिल होता है और इसलिए इसे पूंजी खाते के तहत दर्ज किया जाता है। व्यापार, रेमिटेंस और ब्याज भुगतान चालू खाते (Current Account) में दर्ज किए जाते हैं।



7. Answer: (a)
Explanation: The Suresh Tendulkar Committee, constituted in 2005, recommended a revised methodology for poverty estimation. It moved beyond a purely calorie-based approach and incorporated expenditure on health, education and other essential services.
8. Answer: (c)
Explanation: PMJDY is a flagship financial inclusion programme aimed at providing universal access to banking services. Eligible account holders receive benefits such as a RuPay debit card, accident insurance cover, and access to an overdraft facility, along with basic banking services.
9. Answer: (b)
Explanation: In a Socialist Economy, the state owns or controls major means of production and determines resource allocation. Economic decisions are guided by social welfare objectives rather than profit motives. In contrast, a Mixed Economy combines elements of both state control and market mechanisms.
10. Answer: (b)
Explanation: Purchasing Power Parity (PPP) compares the prices of an identical basket of goods and services across countries. It estimates the exchange rate at which the same basket would cost an equivalent amount in different currencies, thereby accounting for differences in price levels and living costs.
11. Answer: (c)
Explanation: Qualitative monetary policy instruments aim to regulate the direction and use of credit rather than its overall volume. Margin requirements influence borrowing against securities and are therefore selective in nature. CRR, Bank Rate, and OMO are quantitative instruments affecting overall liquidity in the economy.

7. उत्तर: (a)
व्याख्या: 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के अनुमान के लिए एक संशोधित कार्यप्रणाली की सिफारिश की थी। इसने केवल कैलोरी-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं पर होने वाले खर्च को भी इसमें शामिल किया।
8. उत्तर: (c)
व्याख्या: PMJDY वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। योग्य खाताधारकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ RuPay डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसे लाभ मिलते हैं।
9. उत्तर: (b)
व्याख्या: समाजवादी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के मुख्य साधनों पर राज्य का मालिकाना हक या नियंत्रण होता है और वह संसाधनों के बंटवारे को तय करता है। आर्थिक फैसले मुनाफ़े के मकसद के बजाय सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों से प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत, मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य के नियंत्रण और बाजार तंत्र, दोनों के तत्व शामिल होते हैं।
10. उत्तर: (b)
व्याख्या: परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) अलग-अलग देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक जैसी टोकरी (बास्केट) की कीमतों की तुलना करती है। यह उस विनिमय दर का अनुमान लगाती है जिस पर वही टोकरी अलग-अलग मुद्राओं में बराबर कीमत की होगी, जिससे कीमतों के स्तर और जीवन-यापन की लागत में अंतर का पता चलता है।
11. उत्तर: (c)
व्याख्या: गुणात्मक मौद्रिक नीति उपकरणों का मकसद क्रेडिट की कुल मात्रा के बजाय उसकी दिशा और उपयोग को नियंत्रित करना होता है। मार्जिन आवश्यकताएं प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के बदले उधार लेने को प्रभावित करती हैं और इसलिए ये प्रकृति में चयनात्मक होती हैं। CRR, बैंक दर और OMO मात्रात्मक उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था में कुल तरलता (लिक्विडिटी) को प्रभावित करते हैं।

12. Answer: (c)

Explanation: The GST Council was constituted under Article 279A through the 101st Constitutional Amendment Act, 2016. It serves as the apex body for making recommendations on GST-related matters. The Union Finance Minister acts as its Chairperson.

13. Answer: (b)

Explanation: The Second Five-Year Plan was based on the Mahalanobis Model, which prioritized the development of heavy industries and capital goods sectors. The objective was to build a strong industrial base and achieve long-term economic self-reliance.

14. Answer: (b)

Explanation: Foreign Portfolio Investment (FPI) refers to investments in financial instruments such as shares and bonds without seeking managerial control over the enterprise. In contrast, FDI involves a lasting interest and significant influence or control in the management of a business entity.

15. Answer: (c)

Explanation: Disguised unemployment occurs when more workers are engaged in a task than required, resulting in zero marginal productivity for some workers. It is commonly observed in agriculture and informal sectors of developing economies.

16. Answer: (c)

Explanation: PMJJBY is a government-backed life insurance scheme that provides a life cover of ₹2 lakh at a nominal annual premium. It is available to individuals aged 18–50 years having a savings bank account, with coverage renewable annually subject to payment of premium.

17. Answer: (c)

Explanation: Economic growth refers to a sustained increase in a country's real output of goods and services, usually measured through real GDP or real GNP. Economic development is a broader concept encompassing growth along with improvements in education, health, employment, poverty reduction, and overall quality of life.

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

12. उत्तर: (c)

व्याख्या: GST काउंसिल का गठन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत अनुच्छेद 279A के अंतर्गत किया गया था। यह GST से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

13. उत्तर: (b)

व्याख्या: दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसका उद्देश्य एक मज़बूत औद्योगिक आधार बनाना और दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना था।

14. उत्तर: (b)

व्याख्या: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का तात्पर्य उद्यम पर प्रबंधकीय नियंत्रण हासिल किए बिना शेयर और बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों में निवेश से है। इसके विपरीत, FDI में किसी व्यावसायिक इकाई के प्रबंधन में स्थायी हित और महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण शामिल होता है।

15. उत्तर: (c)

व्याख्या: प्रच्छन्न बेरोज़गारी तब होती है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। यह आमतौर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में देखा जाता है।

16. उत्तर: (c)

व्याख्या: PMJJBY सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है जो बहुत कम सालाना प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर देती है। यह 18-50 साल की उम्र के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका सेविंग्स बैंक अकाउंट है; प्रीमियम का भुगतान करने पर इस कवर को हर साल रिन्यू किया जा सकता है।

17. उत्तर: (c)

व्याख्या: आर्थिक वृद्धि का मतलब है किसी देश के सामान और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी, जिसे आमतौर पर वास्तविक GDP या वास्तविक GNP के ज़रिए मापा जाता है। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, गरीबी में कमी और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं।

18. Answer: (b)

Explanation: The Lorenz Curve graphically represents the distribution of income or wealth within a population. The Gini Coefficient, derived from the Lorenz Curve, quantifies the degree of inequality. A value of 0 indicates perfect equality, while a value of 1 indicates perfect inequality.

19. Answer: (a)

Explanation: M1, known as Narrow Money, consists of currency with the public, demand deposits with banks, and other deposits with the RBI. Since these components are highly liquid and readily available for transactions, M1 is considered the narrowest measure of money supply.

20. Answer: (b)

Explanation: Statement 1 is incorrect because the Finance Commission is a constitutional body established under Article 280 of the Constitution. Statement 2 is correct as the Commission recommends the principles governing the distribution of tax proceeds between the Centre and the States.

21. Answer: (b)

Explanation: The National Development Council was established to strengthen cooperative federalism by associating States with the planning process. It served as the highest policy-making body for approving Five-Year Plans and reviewing their implementation.

22. Answer: (c)

Explanation: NEER is a weighted average of a country's bilateral nominal exchange rates against a basket of currencies. REER adjusts the NEER for relative inflation or price level differences between the domestic economy and its trading partners, making it a better indicator of external competitiveness.

RACE IAS General Studies

RACE IAS Rajesh Academy for Civil Examinations



RACE IAS General Studies

RACE IAS Rajesh Academy for Civil Examinations



18. उत्तर: (b)

व्याख्या: लॉरेंज कर्व किसी आबादी के भीतर आय या संपत्ति के वितरण को ग्राफ़ के ज़रिए दिखाता है। लॉरेंज कर्व से निकला गिनी गुणांक असमानता की मात्रा को मापता है। 0 का मान पूरी तरह से समानता को दिखाता है, जबकि 1 का मान पूरी तरह से असमानता को दिखाता है।

19. उत्तर: (a)

व्याख्या: M1, जिसे नैरो मनी के नाम से जाना जाता है, में जनता के पास मौजूद मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉज़िट और RBI के पास अन्य डिपॉज़िट शामिल हैं। चूंकि ये घटक बहुत ज़्यादा लिक्विड (आसानी से नकद में बदले जा सकने वाले) होते हैं और लेन-देन के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए M1 को मुद्रा आपूर्ति का सबसे संकीर्ण (narrowest) माप माना जाता है।

20. उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 सही है क्योंकि आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे के सिद्धांतों की सिफारिश करता है।

21. उत्तर: (b)

व्याख्या: राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना राज्यों को योजना प्रक्रिया से जोड़कर सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए की गई थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय के रूप में कार्य करती थी।

22. उत्तर: (c)

व्याख्या: NEER मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले किसी देश की द्विपक्षीय नॉमिनल विनिमय दरों का भारित औसत है। REER, घरेलू अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच सापेक्ष मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के अंतर के आधार पर NEER को समायोजित करता है, जिससे यह बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता का बेहतर संकेतक बन जाता है।



23. Answer: (a)

Explanation: The Human Poverty Index measured poverty in terms of deprivation of basic capabilities rather than income alone. It focused on three dimensions: longevity (survival), knowledge (literacy), and a decent standard of living, thereby providing a broader assessment of human deprivation.

24. Answer: (c)

Explanation: Beti Bachao Beti Padhao, launched in 2015, is a tri-ministerial initiative aimed at preventing gender-biased sex selection, improving the Child Sex Ratio, and ensuring the survival, protection, education, and empowerment of the girl child. It seeks to promote gender equality through coordinated efforts across sectors.

25. Answer: (c)

Explanation: The Quaternary Sector comprises knowledge-based activities such as research and development, information technology, data processing, education, and consultancy services. It represents the intellectual component of the economy and plays a vital role in innovation and technological advancement.

26. Answer: (b)

Explanation: Core Inflation excludes highly volatile components such as food and fuel from the overall inflation measure. It helps policymakers assess the underlying and persistent inflationary trend in the economy without the influence of temporary price shocks.

27. Answer: (c)

Explanation: The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was established in 1982 to provide credit, refinancing facilities, and institutional support for agriculture, rural industries, and rural infrastructure development. It serves as the apex institution for rural financing in India.

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

23. उत्तर: (a)

व्याख्या: ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ने केवल आय के बजाय बुनियादी क्षमताओं की कमी के आधार पर गरीबी को मापा। इसने तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया: लंबी उम्र (जीवित रहना), ज्ञान (साक्षरता) और जीवन का अच्छा स्तर, जिससे मानवीय अभाव का व्यापक आकलन मिल सके।

24. उत्तर: (c)

व्याख्या: 2015 में शुरू की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' तीन मंत्रालयों की एक पहल है, जिसका उद्देश्य लिंग-आधारित लिंग चयन को रोकना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना और बालिका के जीवित रहने, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

25. उत्तर: (c)

व्याख्या: चतुर्थक क्षेत्र में ज्ञान-आधारित गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा प्रसंस्करण, शिक्षा और परामर्श सेवाएँ। यह अर्थव्यवस्था के बौद्धिक घटक का प्रतिनिधित्व करता है और नवाचार तथा तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

26. उत्तर: (b)

व्याख्या: कोर इन्फ्लेशन कुल मुद्रास्फीति माप से खाद्य और ईंधन जैसे अत्यधिक अस्थिर घटकों को बाहर करता है। यह नीति निर्माताओं को अस्थायी मूल्य झटकों के प्रभाव के बिना अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित और निरंतर मुद्रास्फीति के रुझान का आकलन करने में मदद करता है।

27. उत्तर: (c)

व्याख्या: कृषि, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण, पुनर्वित्त सुविधाएँ और संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना की गई थी। यह भारत में ग्रामीण वित्तपोषण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है।

28. Answer: (b)

Explanation: Primary Deficit indicates the government's current borrowing requirements excluding interest obligations arising from past debt. It is calculated as:

Primary Deficit = Fiscal Deficit – Interest Payments

A zero primary deficit implies that government borrowings are used only to meet interest liabilities.

29. Answer: (a)

Explanation: The First Five-Year Plan was based on the Harrod-Domar Model, which emphasized the role of savings and investment in economic growth. Given India's post-independence challenges, the Plan focused heavily on agriculture, irrigation, and capital formation.

30. Answer: (b)

Explanation: Under a Managed Float Exchange Rate System, exchange rates are primarily determined by demand and supply in the foreign exchange market. However, the central bank may intervene by buying or selling foreign currency to maintain stability and prevent excessive fluctuations.

31. Answer: (c)

Explanation: MGNREGA provides a legal guarantee of at least 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members are willing to undertake unskilled manual work. The scheme aims to enhance livelihood security and reduce rural distress.

32. Answer: (c)

Explanation: AB-PMJAY is a flagship health assurance scheme that provides eligible beneficiary families with annual coverage of up to ₹5 lakh for hospitalization expenses. Services are delivered through a cashless and paperless mechanism at empanelled hospitals across India, reducing out-of-pocket healthcare expenditure.

28. उत्तर: (b)

व्याख्या: प्राथमिक घाटा पिछले ऋण से उत्पन्न ब्याज दायित्वों को छोड़कर सरकार की वर्तमान उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:
प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
शून्य प्राथमिक घाटे का मतलब है कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का इस्तेमाल केवल ब्याज की देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

29. उत्तर: (a)

व्याख्या: पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आर्थिक विकास में बचत और निवेश की भूमिका पर जोर दिया गया था। आजादी के बाद भारत की चुनौतियों को देखते हुए, इस योजना में कृषि, सिंचाई और पूंजी निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया था।

30. उत्तर: (b)

व्याख्या: मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत, एक्सचेंज रेट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा बाज़ार में मांग और सप्लाई से तय होते हैं। हालांकि, सेंट्रल बैंक स्टेबिलिटी बनाए रखने और बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदकर या बेचकर दखल दे सकता है।

31. उत्तर: (c)

व्याख्या: MGNREGA हर उस ग्रामीण परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों के सैलरी-रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इस योजना का मकसद आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना और ग्रामीण संकट को कम करना है।

32. उत्तर: (c)

व्याख्या: AB-PMJAY एक प्रमुख स्वास्थ्य एश्योरेंस योजना है जो योग्य लाभार्थी परिवारों को हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च के लिए सालाना ₹5 लाख तक का कवरेज देती है। सेवाएं पूरे भारत में एम्पैनल्ड अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस तरीकों से दी जाती हैं, जिससे हेल्थकेयर पर होने वाला निजी खर्च कम होता है।

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

33. Answer: (b)

Explanation: Gross Domestic Product (GDP) measures the value of final goods and services produced within a country's domestic territory. Gross National Product (GNP) includes the income earned by a country's residents from abroad and excludes income earned domestically by foreign residents. Therefore:
 $GNP = GDP + \text{Net Factor Income from Abroad (NFIA)}$

34. Answer: (b)

Explanation: Cost-Push Inflation occurs when the cost of production rises due to increases in wages, fuel prices, or raw material costs. Producers pass these higher costs on to consumers through increased prices. Rising crude oil prices often trigger economy-wide inflation because transportation and production costs increase across sectors.

35. Answer: (a)

Explanation: CRR is the percentage of a bank's Net Demand and Time Liabilities (NDTL) that must be maintained with the RBI in the form of cash reserves. SLR is the percentage of NDTL that banks must maintain themselves in liquid assets such as cash, gold, and approved government securities.

36. Answer: (c)

Explanation: Direct taxes are imposed directly on the income or wealth of individuals and organizations, and their burden cannot be shifted to others. Corporate Income Tax is a direct tax. GST and Customs Duty are indirect taxes, as their burden can be passed on to consumers.

37. Answer: (b)

Explanation: The Nehru-Mahalanobis strategy, adopted during the Second Five-Year Plan, emphasized rapid industrialization through the development of heavy industries and capital goods sectors. The objective was to achieve self-reliance and reduce dependence on imported machinery and industrial products.

33. उत्तर: (b)

व्याख्या: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय शामिल होती है और विदेशी निवासियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए:
 $GNP = GDP + \text{विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (NFIA)}$

34. उत्तर: (b)

व्याख्या: लागत-जनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation) तब होती है जब मजदूरी, ईंधन की कीमतों या कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उत्पादक बढ़ी हुई कीमतों के माध्यम से इन बढ़ी हुई लागतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें अक्सर पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ जाती है।

35. उत्तर: (a)

व्याख्या: CRR बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का वह प्रतिशत है जिसे RBI के पास नकद भंडार के रूप में बनाए रखना अनिवार्य है। SLR, NDTL का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को स्वयं तरल परिसंपत्तियों जैसे नकद, सोना और स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है।

36. उत्तर: (c)

व्याख्या: प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्तियों और संगठनों की आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं, और इनका बोझ दूसरों पर नहीं डाला जा सकता। कॉर्पोरेट आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। GST और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर हैं, क्योंकि इनका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है।

37. उत्तर: (b)

व्याख्या: दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई नेहरू-महालनोबिस रणनीति ने भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्रों के विकास के माध्यम से तेजी से औद्योगीकरण पर जोर दिया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयातित मशीनरी और औद्योगिक उत्पादों पर निर्भरता कम करना था।

38. Answer: (b)

Explanation: FERA was enacted during a period of foreign exchange scarcity and focused on strict regulation and conservation of foreign exchange. FEMA, introduced after economic liberalization, shifted the emphasis towards facilitating external trade and payments, and managing foreign exchange in a more market-oriented manner.

39. Answer: (b)

Explanation: PMEGP is a credit-linked subsidy programme implemented by the Ministry of MSME to generate self-employment opportunities through the establishment of micro-enterprises in rural and urban areas. It supports entrepreneurship and employment generation in the non-farm sector.

40. Answer: (a)

Explanation: The Committee on Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low-Income Households, chaired by Dr. Nachiket Mor, was constituted by the RBI in 2013. Its recommendations led to important reforms, including the establishment of Payment Banks and Small Finance Banks to strengthen financial inclusion.

41. Answer: (b)

Explanation: Dadabhai Naoroji made the earliest systematic estimate of India's national income in the late nineteenth century. Through his famous *Drain of Wealth Theory*, he demonstrated how British colonial policies led to the economic exploitation of India and contributed to widespread poverty.

42. Answer: (a)

Explanation: The Producer Price Index (PPI) measures changes in the prices received by producers for goods and services at the production stage. Unlike the Consumer Price Index (CPI), which reflects retail prices paid by consumers, PPI captures price movements from the producers' perspective.

38. उत्तर: (b)

व्याख्या: FERA को विदेशी मुद्रा की कमी के दौर में लागू किया गया था और यह विदेशी मुद्रा के सख्त विनियमन और संरक्षण पर केंद्रित था। आर्थिक उदारीकरण के बाद शुरू किए गए FEMA ने बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और अधिक बाजार-उन्मुख तरीके से विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने पर जोर दिया।

39. उत्तर: (b)

व्याख्या: PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है जिसे MSME मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म-उद्यम (micro-enterprises) स्थापित करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लागू किया गया है। यह गैर-कृषि क्षेत्र में उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।

40. उत्तर: (a)

व्याख्या: डॉ. नचिकेत मोर की अध्यक्षता में छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति का गठन RBI द्वारा 2013 में किया गया था। इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसमें वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना शामिल है।

41. उत्तर: (b)

व्याख्या: दादाभाई नौरोजी ने उन्नीसवीं सदी के अंत में भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहला व्यवस्थित अनुमान लगाया था। अपने प्रसिद्ध 'धन के बहिर्गमन' (Drain of Wealth) सिद्धांत के माध्यम से, उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत का आर्थिक शोषण किया और व्यापक गरीबी में योगदान दिया।

42. उत्तर: (a)

व्याख्या: प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) उत्पादन चरण में वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में बदलाव को मापता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के विपरीत, जो उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली खुदरा कीमतों को दर्शाता है, PPI उत्पादकों के दृष्टिकोण से कीमतों में उतार-चढ़ाव को मापता है।

43. Answer: (a)

Explanation: Moral Suasion involves informal persuasion by the RBI to influence banks. Open Market Operations (OMO) involve the purchase and sale of government securities. Rationing of Credit imposes ceilings on lending, while Consumer Credit Regulation governs the terms and conditions under which consumer loans are provided.

44. Answer: (a)

Explanation: The FRBM Act was enacted to promote fiscal discipline, improve macroeconomic stability, reduce fiscal and revenue deficits, and ensure prudent management of public finances. It established fiscal targets to be achieved by the government over time.

45. Answer: (b)

Explanation: Following the recommendations of the Narasimham Committee, the 1991 reforms opened the banking sector to private and foreign banks. The objective was to enhance efficiency, competition, innovation, and customer service within the financial system.

46. Answer: (c)

Explanation: External Commercial Borrowings (ECBs) are loans raised by Indian companies from international lenders and capital markets. They have historically accounted for a significant share of India's external debt, reflecting the growing integration of Indian businesses with global financial markets.

47. Answer: (b)

Explanation: The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) was established in 1995–96 and is administered by NABARD. It provides financial assistance to State Governments and State-owned entities for developing rural infrastructure such as roads, bridges, irrigation projects, and rural markets.

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

43. उत्तर: (a)

व्याख्या: नैतिक अनुनय (Moral Suasion) में बैंकों को प्रभावित करने के लिए RBI द्वारा अनौपचारिक रूप से समझाना शामिल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है। क्रेडिट की राशनिंग ऋण देने पर सीमा लगाती है, जबकि उपभोक्ता ऋण विनियमन उन शर्तों और नियमों को नियंत्रित करता है जिनके तहत उपभोक्ता ऋण प्रदान किए जाते हैं।

44. उत्तर: (a)

व्याख्या: FRBM एक्ट को राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने, मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता में सुधार करने, राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने और सार्वजनिक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इसने सरकार द्वारा समय के साथ हासिल किए जाने वाले राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किए।

45. उत्तर: (b)

व्याख्या: नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के बाद, 1991 के सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र को निजी और विदेशी बैंकों के लिए खोल दिया। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के भीतर दक्षता, प्रतिस्पर्धा, नवाचार और ग्राहक सेवा को बढ़ाना था।

46. उत्तर: (c)

व्याख्या: बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) वे ऋण हैं जो भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं और पूंजी बाजारों से लेती हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत के बाहरी कर्ज में इनका एक बड़ा हिस्सा रहा है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ भारतीय व्यवसायों के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है।

47. उत्तर: (b)

व्याख्या: ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) की स्थापना 1995-96 में की गई थी और इसका प्रशासन NABARD द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कें, पुल, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण बाजार विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

48. Answer: (a)

Explanation: PMJDY is a financial inclusion programme that provides basic bank accounts. UPI is a real-time payment system developed by NPCI. RuPay is India's domestic card payment network, while NPCI serves as the umbrella organization managing retail payment and settlement systems in the country.

49. Answer: (c)

Explanation: The terms *Microeconomics* and *Macroeconomics* were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch in 1933. Microeconomics studies the behaviour of individual economic units such as consumers and firms, whereas Macroeconomics examines aggregate economic variables such as national income, inflation, unemployment, and economic growth.

50. Answer: (b)

Explanation: Nominal National Income is measured at current prices and may rise due to inflation even when actual output remains unchanged. Real National Income is obtained by eliminating the effect of price changes through a suitable price index or deflator, thereby reflecting the actual increase in output.

51. Answer: (b)

Explanation: Scheduled Commercial Banks are those listed in the Second Schedule of the RBI Act, 1934. Such banks satisfy specific criteria prescribed by the RBI regarding capital, reserves, and financial soundness, and enjoy certain facilities from the Reserve Bank of India.

52. Answer: (a)

Explanation: A Progressive Tax imposes higher rates on higher income groups. A Regressive Tax places a relatively greater burden on lower-income groups. In a Direct Tax, the taxpayer and the person bearing the burden are the same. A Proportional Tax applies a uniform rate across all income levels.

48. उत्तर: (a)

व्याख्या: PMJDY एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो बुनियादी बैंक खाते प्रदान करता है। UPI, NPCI द्वारा विकसित एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है। RuPay भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जबकि NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करने वाले अम्बेला संगठन के रूप में कार्य करता है।

49. उत्तर: (c)

व्याख्या: माइक्रोइकॉनॉमिक्स और मैक्रोइकॉनॉमिक्स शब्द नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रैगनार फ्रिश ने 1933 में दिए थे। माइक्रोइकॉनॉमिक्स में उपभोक्ताओं और फर्मों जैसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रोइकॉनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे कुल आर्थिक चरों की जांच की जाती है।

50. उत्तर: (b)

व्याख्या: नॉमिनल नेशनल इनकम को मौजूदा कीमतों पर मापा जाता है और वास्तविक उत्पादन में कोई बदलाव न होने पर भी मुद्रास्फीति के कारण यह बढ़ सकती है। रियल नेशनल इनकम, उपयुक्त मूल्य सूचकांक या डिफ्लेटर के माध्यम से कीमतों में बदलाव के प्रभाव को हटाकर प्राप्त की जाती है, जिससे उत्पादन में वास्तविक वृद्धि का पता चलता है।

51. उत्तर: (b)

व्याख्या: शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वे हैं जो RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। ऐसे बैंक पूंजी, भंडार और वित्तीय सुदृढ़ता के संबंध में RBI द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

52. उत्तर: (a)

व्याख्या: प्रगतिशील कर अधिक आय वाले समूहों पर उच्च दरें लागू करता है। प्रतिगामी कर कम आय वाले समूहों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालता है। प्रत्यक्ष कर में, करदाता और बोझ उठाने वाला व्यक्ति एक ही होता है। आनुपातिक कर सभी आय स्तरों पर एक समान दर लागू करता है।

53. Answer: (c)

Explanation: The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, 1992 strengthened grassroots democracy by granting constitutional status to Panchayats and Municipalities. Article 243ZD mandates the constitution of District Planning Committees to integrate rural and urban development plans at the district level.

54. Answer: (c)

Explanation: NRI deposits constitute liabilities of Indian banks and therefore represent debt-creating capital inflows. They are recorded under the Capital Account of the Balance of Payments. Unlike remittances, they are repayable along with interest and hence create future obligations.

55. Answer: (a)

Explanation: PMAY-U aims to provide affordable housing in urban areas. AMRUT focuses on essential urban infrastructure such as water supply and sewerage systems. The Smart Cities Mission promotes technology-enabled urban governance and sustainable development, while HRIDAY is dedicated to preserving the heritage character of selected cities.

56. Answer: (b)

Explanation: The Committee on Digital Payments, chaired by Ratan P. Watal, was established to promote digital transactions and reduce dependence on cash. It recommended measures relating to payment infrastructure, regulatory reforms, consumer protection, and the expansion of digital financial services.

57. Answer: (b)

Explanation: Gross Fixed Capital Formation (GFCF) measures investment in fixed physical assets such as machinery, factories, roads, bridges, and transport equipment. It is an important indicator of capital formation, productive capacity, and future economic growth.

53. उत्तर: (c)

व्याख्या: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत किया। अनुच्छेद 243ZD जिला स्तर पर ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं को एकीकृत करने के लिए जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है।

54. उत्तर: (c)

व्याख्या: NRI जमा भारतीय बैंकों की देनदारियां होती हैं और इसलिए ये कर्ज पैदा करने वाले पूंजी प्रवाह को दर्शाती हैं। इन्हें 'बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स' के पूंजी खाते के तहत दर्ज किया जाता है। रेमिटेंस (विदेश से भेजी गई रकम) के विपरीत, इन्हें ब्याज सहित वापस करना होता है और इसलिए ये भविष्य की देनदारियां पैदा करती हैं।

55. उत्तर: (a)

व्याख्या: PMAY-U का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराना है। AMRUT जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम जैसे आवश्यक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करता है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन तकनीक-सक्षम शहरी प्रशासन और सतत विकास को बढ़ावा देता है, जबकि HRIDAY चुनिंदा शहरों की विरासत की विशेषता को संरक्षित करने के लिए समर्पित है।

56. उत्तर: (b)

व्याख्या: रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान समिति की स्थापना डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और नकदी पर निर्भरता कम करने के लिए की गई थी। इसने भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर, नियामक सुधार, उपभोक्ता संरक्षण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से संबंधित उपायों की सिफारिश की।

57. उत्तर: (b)

व्याख्या: ग्राँस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF) मशीनरी, कारखानों, सड़कों, पुलों और परिवहन उपकरणों जैसी फिक्स्ड फिजिकल एसेट्स (स्थायी भौतिक संपत्तियों) में निवेश को मापता है। यह पूंजी निर्माण, उत्पादन क्षमता और भविष्य की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

58. Answer: (c)

Explanation: Demand-Pull Inflation arises when aggregate demand exceeds aggregate supply. To curb excess demand, the government may adopt contractionary fiscal policy by increasing taxes, while the RBI may implement contractionary monetary policy by raising the Repo Rate, thereby reducing liquidity and credit demand.

59. Answer: (b)

Explanation: The merger of Public Sector Banks was aimed at creating globally competitive banking institutions with stronger balance sheets, better capital utilization, enhanced risk management, and greater ability to finance large-scale infrastructure and industrial projects.

60. Answer: (b)

Explanation: GST subsumed multiple indirect taxes and introduced a seamless Input Tax Credit (ITC) mechanism across the value chain. This removed the cascading effect of taxes, commonly referred to as the "tax-on-tax" problem, thereby improving efficiency and reducing the overall tax burden.

61. Answer: (b)

Explanation: In 1991, India faced a severe Balance of Payments crisis, with foreign exchange reserves falling to levels sufficient for only a few weeks of imports. This compelled the government to undertake structural reforms and seek assistance from international financial institutions.

62. Answer: (b)

Explanation: The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), under the Ministry of Commerce and Industry, is responsible for implementing the Foreign Trade Policy (FTP), promoting exports, issuing trade-related authorizations, and facilitating international trade.

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

58. उत्तर: (c)

व्याख्या: डिमांड-पुल इन्फ्लेशन तब उत्पन्न होती है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। अत्यधिक मांग को रोकने के लिए, सरकार कर बढ़ाकर संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपना सकती है, जबकि RBI रेपो रेट बढ़ाकर संकुचनकारी मौद्रिक नीति लागू कर सकता है, जिससे तरलता और ऋण की मांग कम हो जाती है।

59. उत्तर: (b)

व्याख्या: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का उद्देश्य मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर पूंजी उपयोग, बेहतर जोखिम प्रबंधन और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की अधिक क्षमता वाले विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंकिंग संस्थान बनाना था।

60. उत्तर: (b)

व्याख्या: GST ने कई इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक आसान इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सिस्टम शुरू किया। इससे टैक्स का कैस्केडिंग असर (जिसे आम तौर पर "टैक्स-ऑन-टैक्स" समस्या कहा जाता है) खत्म हो गया, जिससे काम करने की क्षमता बेहतर हुई और कुल टैक्स का बोझ कम हुआ।

61. उत्तर: (b)

व्याख्या: 1991 में भारत को बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि उससे कुछ हफ्तों का ही आयात हो सकता था। इस वजह से सरकार को स्ट्रक्चरल सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

62. उत्तर: (b)

व्याख्या: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT), जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, विदेश व्यापार नीति (FTP) को लागू करने, निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापार से जुड़े अधिकार-पत्र जारी करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए ज़िम्मेदार है।

63. Answer: (a)

Explanation: Samagra Shiksha is an integrated school education programme from pre-school to Class XII. RUSA supports higher education institutions. PM-POSHAN provides nutritious meals to school children, while RMSA was designed to improve access, equity, and quality in secondary education.

64. Answer: (b)

Explanation: The Narasimham Committees laid the foundation for banking sector reforms in India. Their recommendations included reducing CRR and SLR, strengthening prudential norms, introducing capital adequacy requirements, improving asset quality management, deregulating interest rates, and encouraging competition through the entry of private sector banks.

65. Answer: (b)

Explanation:

When measured at market exchange rates, India stands as the world's fifth-largest economy. However, when evaluated on a Purchasing Power Parity (PPP) basis—which accounts for the local costs of goods and services—India ranks third globally, trailing only China (first) and the United States (second).

66. Answer: (c)

Explanation:

Stagflation is an unconventional economic situation where a high rate of inflation is accompanied by slow economic growth and high unemployment. It contradicts the traditional short-run Phillips Curve model, which posits that high inflation typically accompanies low unemployment. It is frequently triggered by major cost-push supply shocks, such as a sharp spike in international fuel prices.

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

63. उत्तर: (a)

व्याख्या: समग्र शिक्षा प्री-स्कूल से कक्षा XII तक का एक एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है। RUSA उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। PM-POSHAN स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि RMSA को माध्यमिक शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया था।

64. उत्तर: (b)

व्याख्या: नरसिम्हम समितियों ने भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की नींव रखी। उनकी सिफारिशों में CRR और SLR को कम करना, विवेकपूर्ण मानदंडों (prudential norms) को मजबूत करना, पूंजी पर्याप्तता (capital adequacy) की आवश्यकताएं लागू करना, परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार करना, ब्याज दरों को विनियंत्रण (deregulate) करना और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल था।

65. उत्तर: (b)

व्याख्या:

बाजार विनिमय दरों पर मापे जाने पर, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि, जब क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है—जो वस्तुओं और सेवाओं की स्थानीय लागत को ध्यान में रखता है—तो भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर आता है, और केवल चीन (पहला) और संयुक्त राज्य अमेरिका (दूसरा) से पीछे है।

66. उत्तर: (c)

व्याख्या:

स्टैगफ्लेशन एक असामान्य आर्थिक स्थिति है जहां उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है। यह पारंपरिक अल्पकालिक फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) मॉडल के विपरीत है, जो यह मानता है कि उच्च मुद्रास्फीति आमतौर पर कम बेरोजगारी के साथ होती है। यह अक्सर प्रमुख लागत-जनित आपूर्ति झटकों (cost-push supply shocks) के कारण होता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि।

67. Answer: (c)

Explanation:

The Capital Adequacy Ratio (CAR), or Capital-to-Risk Weighted Assets Ratio (CRAR), is a metric measuring a bank's available capital expressed as a percentage of its risk-weighted credit exposures. This statutory cushion ensures that financial institutions have enough capital to absorb a reasonable amount of loan losses, protecting depositors and maintaining broader banking framework stability.

68. Answer: (c)

Explanation:

Revenue Expenditure includes expenses that do not result in the creation of physical or financial assets, nor do they reduce government liabilities. Examples include interest payments, salaries, pensions, subsidies, and grants to states. Loans given to states, land acquisition, and defense equipment purchases are classified as Capital Expenditure because they create long-term assets or decrease liabilities.

69. Answer: (b)

Explanation:

Imperative planning (or command planning) involves a centralized authority that dictates production quotas, pricing, and distribution with absolute legal enforcement, as observed historically in the USSR. Indicative planning, which India gradually transitioned toward after its economic liberalization, sets broad macroeconomic directions and targets, relying on fiscal tools and collaborative incentives to guide the private and public sectors.

70. Answer: (b)

Explanation:

The National Social Assistance Programme (NSAP) was launched on August 15, 1995. It represents a significant step toward fulfilling the Directive Principles of State Policy enshrined in Article 41 of the Indian Constitution. NSAP provides financial assistance to the elderly, widows, and persons with disabilities living below the poverty line through programs like the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS).

67. उत्तर: (c)

व्याख्या:

कैपिटल एडिक्वैसी रेश्यो (CAR), या कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो (CRAR), एक ऐसा पैमाना है जो बैंक की उपलब्ध पूंजी को उसके रिस्क-वेटेड क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में मापता है। यह कानूनी सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय संस्थानों के पास लोन से होने वाले नुकसान को झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी हो, जिससे जमाकर्ताओं की सुरक्षा हो और बैंकिंग सिस्टम में स्थिरता बनी रहे।

68. उत्तर: (c)

व्याख्या:

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वे खर्च शामिल होते हैं जिनसे न तो कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट बनता है और न ही सरकारी देनदारियां कम होती हैं। इसके उदाहरणों में ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं। राज्यों को दिए गए लोन, ज़मीन अधिग्रहण और डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इनसे लंबे समय तक चलने वाले एसेट बनते हैं या देनदारियां कम होती हैं।

69. उत्तर: (b)

व्याख्या:

इंपेरेटिव प्लानिंग (या कमांड प्लानिंग) में एक सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी होती है जो प्रोडक्शन कोटा, कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी कानूनी सख्ती के साथ तय करती है, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से USSR में देखा गया था। सांकेतिक नियोजन, जिसकी ओर भारत ने आर्थिक उदारीकरण के बाद धीरे-धीरे संक्रमण किया, व्यापक मैक्रोइकॉनॉमिक दिशा-निर्देश और लक्ष्य निर्धारित करता है, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को निर्देशित करने के लिए राजकोषीय उपकरणों और सहयोगात्मक प्रोत्साहनों पर निर्भर करता है।

70. उत्तर: (b)

व्याख्या:

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में शामिल राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NSAP, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

71. Answer: (a)

Explanation:

Special Economic Zones (SEZs) act as duty-free, foreign-territory-equivalent pockets designed to attract export-oriented foreign direct investment. The EPCG scheme allows exporters to import advanced capital machinery at zero duty, conditional on a corresponding export obligation. The RoDTEP scheme covers embedded local duties and levies that are otherwise non-refundable. The Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) bridges gaps in physical infrastructure to assist export growth.

72. Answer: (b)

Explanation:

The Committee on Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low-Income Households (chaired by Dr. Nachiket Mor) submitted its report to the RBI in 2014. The committee recommended a "differentiated banking design" rather than a uniform model. This led to the introduction of Payment Banks (handling remittance and small deposits without lending) and Small Finance Banks (providing basic credit to small farmers and MSMEs) to accelerate financial inclusion.

73. Answer: (d)

Explanation:

The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) transitioned to this updated base year to accurately reflect post-pandemic structural shifts, the formalization of the economy, and the growing digital and gig sectors. This new series replaced the older 2011-12 base year.

74. Answer: (b)

Explanation:

Headline inflation calculates the total inflation in an economy, inclusive of highly volatile food and energy/fuel prices. Core inflation excludes food and fuel to show the underlying, long-term price trends without seasonal or global supply shocks.

RACE IAS General Studies**RACE IAS** General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations**RACE IAS** General Studies**RACE IAS** General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

71. उत्तर: (a)

व्याख्या:

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) शुल्क-मुक्त, विदेशी क्षेत्र के बराबर ऐसे क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें निर्यात-उन्मुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। EPCG योजना निर्यातकों को संबंधित निर्यात दायित्व की शर्त पर शून्य शुल्क पर उन्नत पूंजीगत मशीनरी आयात करने की अनुमति देती है। RoDTEP स्कीम में ऐसे लोकल टैक्स और लेवी शामिल हैं जो आम तौर पर रिफंडेबल नहीं होते हैं। 'ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम' (TIES) एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करती है।

72. उत्तर: (b)

व्याख्या:

छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर बनी कमिटी (जिसकी अध्यक्षता डॉ. नचिकेत मोर ने की थी) ने 2014 में RBI को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी ने एक जैसे मॉडल के बजाय "अलग-अलग बैंकिंग डिज़ाइन" का सुझाव दिया। इससे फाइनेंशियल इन्क्लूजन (वित्तीय समावेशन) को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट बैंक (जो बिना लोन दिए रेमिटेंस और छोटे डिपॉजिट को संभालते हैं) और स्मॉल फाइनेंस बैंक (जो छोटे किसानों और MSMEs को बेसिक क्रेडिट देते हैं) की शुरुआत हुई।

73. उत्तर: (d)

व्याख्या:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने महामारी के बाद आए स्ट्रक्चरल बदलावों, अर्थव्यवस्था के औपचारिक होने और बढ़ते डिजिटल और गिग सेक्टर को सही ढंग से दिखाने के लिए इस अपडेटेड आधार वर्ष को अपनाया। इस नई सीरीज़ ने पुराने 2011-12 आधार वर्ष की जगह ली।

74. उत्तर: (b)

व्याख्या:

हेडलाइन महंगाई दर अर्थव्यवस्था में कुल महंगाई को मापती है, जिसमें भोजन और ऊर्जा/ईंधन की बहुत ज़्यादा अस्थिर कीमतें भी शामिल होती हैं। कोर महंगाई दर में भोजन और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है ताकि मौसमी या ग्लोबल सप्लाय शॉक के बिना कीमतों के मूल, लंबे समय के ट्रेंड को दिखाया जा सके।



75. Answer: (c)

Explanation:

Payment banks are a category of differentiated banks introduced by the RBI to promote financial inclusion. They can accept limited deposits and issue debit cards, but they are strictly barred from undertaking lending activities or issuing credit cards.

76. Answer: (b)

Explanation:

Deficit financing occurs when a government borrows money or prints currency to cover its budgetary shortfall. This process injects new money into the system, increasing aggregate demand, which typically leads to an increase in the price level (inflation).

77. Answer: (a)

Explanation:

The Twelfth Five Year Plan (2012–2017) was the last official Five-Year Plan of India before the Planning Commission was replaced by NITI Aayog. Its designated vision statement was "Faster, Sustainable and More Inclusive Growth."

78. Answer: (b)

Explanation:

The S.S. Tarapore Committee was constituted by the Reserve Bank of India in 1997 and 2006 to lay out a structural roadmap and evaluate conditions for full Capital Account Convertibility (CAC) in India.

79. Answer: (a)

Explanation:

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched on August 28, 2014. It is a National Mission on Financial Inclusion designed to provide universal banking access to unbanked households across India.

75. उत्तर: (सी)

व्याख्या:

बैंक, आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंकों की एक श्रेणी शुरू की गई है। वे सीमित जमा स्वीकार कर सकते हैं और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उधार ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी करने से पूरी तरह से छूट मिल गई है।

76. उत्तर: (बी)

व्याख्या:

जब सरकार अपने बजटीय वित्त-व्यवस्था को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेती है या मुद्रा छापती है, तो यह तब होता है जब सरकार अपने बजटीय वित्त-व्यवस्था को पूरा करती है। यह प्रक्रिया सिस्टम में नया पैसा लाती है, जिससे कुल मांग बढ़ती है, और आम तौर पर स्तर स्तर मूल्य (महंगाई) में वृद्धि होती है।

77. उत्तर: (ए)

व्याख्या:

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) योजना आयोग की जगह नीति आयोग के आने से पहले भारत की अंतिम आधिकारिक पंचवर्षीय योजना थी। इसमें विज्ञान सुपरमार्केट "तेज़, स्थिरता और अधिक समावेशी विकास" शामिल था।

78. उत्तर: (बी)

व्याख्या:

एस.एस. तारापोर समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1997 और 2006 में भारत में पूर्ण पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता (सीएसी) के लिए एक कम्म रोडमैप तैयार करने और आधार का आकलन करने के लिए किया गया था।

79. उत्तर: (a)

व्याख्या:

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई थी। यह वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे पूरे भारत में उन परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनकी बैंकिंग तक पहुँच नहीं थी।

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations



RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations



80. Answer: (a)

Explanation:

The Deepak Mohanty Committee (2015) outlined the medium-term roadmap for financial inclusion. The Nachiket Mor Committee (2014) recommended setting up differentiated entities like Payment Banks. The Urjit Patel Committee (2014) introduced flexible inflation targeting. The Bimal Jalan Committee (2019) reviewed the economic capital framework and contingency reserves held by the RBI.

81. Answer: (c)

Explanation: The Government of India merged the Central Statistics Office (CSO) and the National Sample Survey Office (NSSO) in 2019 to create the National Statistical Office (NSO). The NSO functions under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) and serves as the apex statistical agency of the country.

82. Answer: (c)

Explanation: The GDP Deflator measures the change in prices of all final goods and services produced within an economy. It is calculated as the ratio of Nominal GDP to Real GDP and is widely used to assess the impact of inflation on economic output.

83. Answer: (b)

Explanation: The Banking Ombudsman is appointed by the Reserve Bank of India (RBI) to address customer grievances relating to banking services. Since 2021, the Banking Ombudsman Scheme has been integrated into the RBI's Integrated Ombudsman Scheme for a unified grievance redressal mechanism.

84. Answer: (a)

Explanation: Article 275 empowers Parliament to provide grants-in-aid from the Consolidated Fund of India to States requiring financial assistance. Such grants are intended to promote balanced regional development and support the welfare of Scheduled Tribes and other disadvantaged areas.

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

80. उत्तर: (a)

व्याख्या:

दीपक मोहंती समिति (2015) ने वित्तीय समावेशन के लिए मध्यम-अवधि का रोडमैप तैयार किया। नचिकेत मोर समिति (2014) ने पेमेंट बैंक जैसी विशिष्ट संस्थाएँ स्थापित करने की सिफारिश की। उर्जित पटेल समिति (2014) ने लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण शुरू किया। बिमल जालान समिति (2019) ने RBI के आर्थिक पूंजी ढांचे और आकस्मिक भंडार की समीक्षा की।

81. उत्तर: (c)

व्याख्या: भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (CSO) और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) को मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) बनाया। NSO, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के तहत काम करता है और देश की मुख्य सांख्यिकीय एजेंसी के तौर पर काम करता है।

82. उत्तर: (c)

व्याख्या: GDP डिफ्लेटर किसी अर्थव्यवस्था में बनने वाले सभी अंतिम सामानों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसे नॉमिनल GDP और रियल GDP के अनुपात के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है और आर्थिक आउटपुट पर महंगाई के असर का पता लगाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।

83. उत्तर: (b)

व्याख्या: बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति करता है। 2021 से, बैंकिंग लोकपाल योजना को शिकायतों के समाधान के एक एकीकृत सिस्टम के लिए RBI की एकीकृत लोकपाल योजना में मिला दिया गया है।

84. उत्तर: (a)

व्याख्या: अनुच्छेद 275 संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत की संघित निधि (Consolidated Fund of India) से उन राज्यों को सहायता-अनुदान दे जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ऐसे अनुदानों का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण में सहायता करना है।



85. Answer: (a)

Explanation: The Bombay Plan was drafted in 1944 by a group of leading Indian industrialists, including J.R.D. Tata, G.D. Birla, and Purshottamdas Thakurdas. It advocated state-led industrialization, planned economic development, and substantial public investment in infrastructure.

86. Answer: (b)

Explanation: Engineering goods constitute the largest share of India's merchandise exports. This category includes machinery, transport equipment, industrial products, automobiles, and engineering components, making it a major contributor to India's export earnings.

87. Answer: (b)

Explanation: The Atal Pension Yojana (APY) was launched in May 2015 to provide a guaranteed pension to workers in the unorganized sector. Subscribers receive a fixed monthly pension after attaining 60 years of age, based on their contributions during the accumulation phase.

88. Answer: (c)

Explanation: The P.J. Nayak Committee (2014) was established to examine governance issues in Public Sector Banks. It recommended reducing government interference, strengthening bank boards, improving professional management, and enhancing operational autonomy to improve efficiency and competitiveness.

89. Answer: (b)

Explanation: The Phillips Curve is an economic concept developed by A.W. Phillips showing that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. According to this theory, higher inflation is associated with lower unemployment, and vice versa, as economic growth creates jobs but drives up wages and prices.

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations

85. उत्तर: (a)

व्याख्या: बॉम्बे प्लान का मसौदा 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला और पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास शामिल थे। इसने राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगीकरण, नियोजित आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश की वकालत की।

86. उत्तर: (b)

व्याख्या: भारत के माल निर्यात में इंजीनियरिंग सामान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस श्रेणी में मशीनरी, परिवहन उपकरण, औद्योगिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग घटक शामिल हैं, जो इसे भारत की निर्यात आय में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाते हैं।

87. उत्तर: (b)

व्याख्या: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए मई 2015 में अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की गई थी। अंशधारकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलती है, जो संचय चरण (accumulation phase) के दौरान उनके योगदान पर आधारित होती है।

88. उत्तर: (c)

व्याख्या: P.J. नायक समिति (2014) का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। इसने दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए सरकारी दखल कम करने, बैंक बोर्ड को मजबूत करने, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में सुधार करने और ऑपरेशनल स्वायत्तता (कामकाज में आजादी) बढ़ाने की सिफारिश की थी।

89. उत्तर: (b)

व्याख्या: फिलिप्स कर्व एक आर्थिक अवधारणा है जिसे A.W. फिलिप्स ने विकसित किया था। यह दिखाता है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर और उल्टा संबंध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, अधिक महंगाई कम बेरोजगारी से जुड़ी होती है और इसके विपरीत भी, क्योंकि आर्थिक विकास से नौकरियां तो पैदा होती हैं लेकिन साथ ही मजदूरी और कीमतें भी बढ़ती हैं।

90. Answer: (b)

Explanation:

Following the recommendations of the All India Rural Credit Survey Committee (Gorewala Committee), the government passed the State Bank of India Act in 1955. This act nationalized the Imperial Bank of India and renamed it the State Bank of India on July 1, 1955, creating a premier public sector banking entity.

91. Answer: (a)

Explanation:

The Gandhian Plan was drafted by Principal Shriman Narayan Agarwal in 1944. Grounded in Mahatma Gandhi's economic philosophy, it favored a bottom-up approach, rural self-sufficiency, and small-scale cottage industries, directly contrasting with the heavy industrialization focus of the concurrent Bombay Plan.

92. Answer: (b)

Explanation:

Following the recommendations of the Urjit Patel Committee in 2014, the Reserve Bank of India shifted away from the Wholesale Price Index (WPI) and officially adopted the Consumer Price Index (CPI) Combined as its primary indicator to guide inflation targeting and monetary policy actions.

93. Answer: (b)

Explanation:

According to Article 279A, every decision of the GST Council requires a three-fourths (75%) majority of the weighted votes cast. The Central Government holds a one-third (33.3%) weight of the total votes cast, while all State Governments combined hold the remaining two-thirds (66.7%) weight.

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations



RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations



90. उत्तर: (b)

व्याख्या:

ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी (गोरेवाला कमेटी) की सिफारिशों के बाद, सरकार ने 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख बैंकिंग संस्था बनी।

91. उत्तर: (a)

व्याख्या:

गांधियन योजना का मसौदा 1944 में प्रिंसिपल श्रीमन् नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा पर आधारित इस योजना में 'बॉटम-अप' (निचले स्तर से ऊपर की ओर) दृष्टिकोण, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों का समर्थन किया गया था। यह उस समय की बॉम्बे योजना के भारी औद्योगीकरण पर केंद्रित दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत थी।

92. उत्तर: (b)

व्याख्या:

2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का इस्तेमाल बंद कर दिया और आधिकारिक तौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) संयुक्त को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मौद्रिक नीति से जुड़े फैसले लेने के लिए अपने मुख्य संकेतक के रूप में अपनाया।

93. उत्तर: (b)

व्याख्या:

अनुच्छेद 279A के अनुसार, GST काउंसिल के हर फैसले के लिए डाले गए भारित मतों (weighted votes) का तीन-चौथाई (75%) बहुमत आवश्यक है। कुल डाले गए मतों में केंद्र सरकार का भार एक-तिहाई (33.3%) होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों का कुल भार शेष दो-तिहाई (66.7%) होता है।



94. Answer: (a)

Explanation:

The Twenty Point Programme was launched in 1975 to alleviate poverty. The Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) started in 1993 under the Ministry of Statistics and Programme Implementation. Both Stand-Up India (supporting entrepreneurship among SC/ST and women) and Mahila E-Haat (an online marketing platform for women entrepreneurs) were launched in 2016.

95. Answer: (b)

Explanation:

The Most Favored Nation (MFN) principle is a core pillar of the WTO trading system. It dictates that WTO member countries cannot normally discriminate between their trading partners. If a country grants someone a special favor (such as a lower customs duty rate for one of their products), they must do the same for all other WTO members.

96. Answer: (b)

Explanation:

Market Infrastructure Institutions (MIIs) are institutions that provide the critical infrastructure required for the smooth trading, settlement, and clearing of securities in the capital market. Key examples include stock exchanges (like BSE and NSE), depositories (CDSL and NSDL), and clearing corporations. They are stringently regulated by SEBI due to their systemic importance.

97. Answer: (b)

Explanation:

Green accounting integrates economic and environmental data. It measures the depletion of natural resources and environmental degradation costs, adjusting the traditional Net Domestic Product (NDP) to calculate the "Green GDP" or Environmentally-adjusted Net Domestic Product (EDP).

RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations



RACE IAS
General Studies

RACE IAS
Rajesh Academy for Civil Examinations



94. उत्तर: (a)

व्याख्या:

बीस सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए 1975 में शुरू किया गया था। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) 1993 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। स्टैंड-अप इंडिया (SC/ST और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली) और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म) दोनों 2016 में शुरू की गई थीं।

95. उत्तर: (b)

व्याख्या:

"मोस्ट फेवर्ड नेशन" (MFN) सिद्धांत WTO व्यापार प्रणाली का एक मुख्य स्तंभ है। यह नियम तय करता है कि WTO सदस्य देश आम तौर पर अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। यदि कोई देश किसी को विशेष सुविधा देता है (जैसे कि किसी उत्पाद के लिए कम कस्टम ड्यूटी दर), तो उसे अन्य सभी WTO सदस्यों के लिए भी वैसा ही करना होगा।

96. उत्तर: (b)

व्याख्या:

बाजार अवसंरचना संस्थान (MII) वे संस्थान हैं जो पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों (सिक्क्योरिटीज) के सुचारू व्यापार, निपटान (सेटलमेंट) और क्लियरिंग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। प्रमुख उदाहरणों में स्टॉक एक्सचेंज (जैसे BSE और NSE), डिपॉजिटरी (CDSL और NSDL) और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शामिल हैं। प्रणालीगत महत्व के कारण SEBI द्वारा इन्हें सख्ती से रेगुलेट किया जाता है।

97. उत्तर: (b)

व्याख्या:

ग्रीन अकाउंटिंग आर्थिक और पर्यावरणीय डेटा को एकीकृत करती है। यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण क्षरण की लागत को मापती है, और "ग्रीन GDP" या पर्यावरण-समायोजित शुद्ध घरेलू उत्पाद (EDP) की गणना करने के लिए पारंपरिक शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) को समायोजित करती है।

98. Answer: (c)

Explanation:

The 'Threshold Inflation Rate' is the optimal level of inflation up to which price rises act as a stimulant for investment and economic growth. Beyond this critical threshold, inflation turns harmful, eroding purchasing power and disrupting investment stability.

99. Answer: (b)

Explanation:

White Label ATMs (WLAs) are owned and operated by non-bank entities. They permit cardholders of any bank to use banking services. Conversely, Brown Label ATMs are owned by a bank but their hardware and lease operations are outsourced to a third party.

100. Answer: (c)

Explanation:

Capital receipts are divided into debt receipts (loans that create liabilities) and non-debt receipts (which liquidate assets without adding liability). Recovery of loans reduces an asset but does not create a future debt liability, classifying it as a non-debt capital receipt.

101. Answer: (b)

Explanation:

Established in August 1952, the National Development Council (NDC) served as the highest decision-making authority in India's planning era. While the Planning Commission prepared the drafts, the NDC—composed of the Prime Minister and State Chief Ministers—had the final authority to review and approve the Five-Year Plans.

102. Answer: (c)

Explanation:

Import cover measures the number of months of imports that a country's official foreign exchange reserves can purchase at any given point. It is a vital indicator used by global rating agencies to evaluate a country's balance of payments resilience.

98. उत्तर: (c)

व्याख्या:

'थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन रेट' मुद्रास्फीति का वह आदर्श स्तर है जहाँ तक कीमतों में वृद्धि निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इस महत्वपूर्ण सीमा से आगे बढ़ने पर, मुद्रास्फीति हानिकारक हो जाती है, जिससे क्रय शक्ति कम होती है और निवेश की स्थिरता बाधित होती है।

99. उत्तर: (b)

व्याख्या:

व्हाइट लेबल ATM (WLAs) का स्वामित्व और संचालन गैर-बैंकिंग संस्थाओं के पास होता है। ये किसी भी बैंक के कार्डधारकों को बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। इसके विपरीत, ब्राउन लेबल ATM का स्वामित्व बैंक के पास होता है, लेकिन उनके हार्डवेयर और लीज़ संचालन को किसी तीसरी पार्टी को आउटसोर्स किया जाता है।

100. उत्तर: (c)

व्याख्या:

पूंजी प्राप्तियों को ऋण प्राप्तियों (वे ऋण जो देनदारियां पैदा करते हैं) और गैर-ऋण प्राप्तियों (जो बिना देनदारी बढ़ाए संपत्ति को समाप्त करती हैं) में विभाजित किया जाता है। ऋणों की वसूली से संपत्ति कम होती है लेकिन भविष्य में कोई ऋण देनदारी पैदा नहीं होती, इसलिए इसे गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

101. उत्तर: (b)

व्याख्या:

अगस्त 1952 में स्थापित, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) भारत के योजना काल में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था थी। जहाँ योजना आयोग मसौदा तैयार करता था, वहीं NDC—जिसमें प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे—के पास पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें मंजूरी देने का अंतिम अधिकार था।

102. उत्तर: (c)

व्याख्या:

इंपोर्ट कवर यह मापता है कि किसी देश का आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी समय कितने महीनों के आयात का खर्च उठा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां किसी देश के 'बैलेंस ऑफ़ पेमेंट्स' (भुगतान संतुलन) की मज़बूती का आकलन करने के लिए करती हैं।

103. Answer: (a)

Explanation:

The unorganized sector scheme RSBY rolled out in 2008. The personal accident insurance scheme PMSBY was introduced in 2015. The flagship health cover PMJAY launched in 2018, and the comprehensive saturation health initiative Ayushman Bhavah campaign was introduced in 2023.

104. Answer: (b)

Explanation:

The term "Budget" does not appear in the Indian Constitution. Instead, Article 112 mandates that the government present an "Annual Financial Statement" showing estimated receipts and expenditures for that financial year before both Houses of Parliament.

105. Answer: (b)

Explanation:

Statement 1 is incorrect because the agriculture and allied sector in India typically grows at an average rate of 3% to 4% per annum, fluctuating due to monsoon dependencies, rather than maintaining an 8% growth rate. Statement 2 is correct; as per recent Periodic Labour Force Survey (PLFS) data, agriculture remains the largest absorbing sector of employment in India, providing livelihoods to over 45% of the workforce.

106. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct. The services sector is the primary driver of India's economic growth, consistently contributing over 50% to India's total GVA. Driven by software, IT services, and business services, India has also established itself firmly as one of the top ten service exporters in the global trade arena.

103. उत्तर: (a)

व्याख्या:

असंगठित क्षेत्र की योजना RSBY 2008 में शुरू की गई थी। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PMSBY 2015 में शुरू की गई थी। प्रमुख स्वास्थ्य कवर PMJAY 2018 में लॉन्च किया गया था, और व्यापक सैचुरेशन स्वास्थ्य पहल 'आयुष्मान भव अभियान' 2023 में शुरू किया गया था।

104. उत्तर: (b)

व्याख्या:

भारतीय संविधान में "बजट" शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, अनुच्छेद 112 यह अनिवार्य करता है कि सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला "वार्षिक वित्तीय विवरण" प्रस्तुत करे।

105. उत्तर: (b)

व्याख्या:

कथन 1 गलत है क्योंकि भारत में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की विकास दर आमतौर पर औसतन 3% से 4% प्रति वर्ष रहती है (मानसून पर निर्भरता के कारण इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है), न कि 8%। कथन 2 सही है; हालिया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आंकड़ों के अनुसार, कृषि भारत में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है और कुल कार्यबल के 45% से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है।

106. उत्तर: (c)

व्याख्या:

दोनों कथन सही हैं। सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि का मुख्य चालक है और भारत के कुल GVA में लगातार 50% से अधिक का योगदान देता है। सॉफ्टवेयर, IT सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं के दम पर, भारत ने वैश्विक व्यापार जगत में शीर्ष दस सेवा निर्यातकों में से एक के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

107. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct; recent Indian Union Budgets and Economic Surveys highlight a major strategic shift toward increasing capital expenditure to build assets like railways, highways, and logistics parks. Statement 2 is incorrect because capital expenditure creates physical assets and long-term productive capacity, thereby carrying a much higher economic multiplier effect (around 2.5 to 4.5) than revenue expenditure (which is closer to 1).

108. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct; the Eight Core Industries (Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement, and Electricity) make up approximately 40.27% of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). Statement 2 is incorrect because Refinery Products holds the highest individual weight among the core industries, followed by Electricity and Steel.

109. Answer: (b)

Explanation:

India is the world's largest recipient of inward remittances, breaking records by capturing substantial cross-border financial flows sent home by its vast overseas diaspora. This capital inflow serves as a vital cushion for India's Current Account Balance.

110. Answer: (c)

Explanation:

The United States of America (USA) has emerged as India's top trading partner in terms of bilateral goods and services trade, frequently switching the top position with China, but offering a unique advantage as India maintains a trade surplus with the USA.

107. उत्तर: (a)

व्याख्या:

कथन 1 सही है; हाल के भारतीय केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षणों में रेलवे, हाईवे और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी संपत्तियां बनाने के लिए पूंजीगत व्यय (capital expenditure) बढ़ाने की दिशा में एक बड़े रणनीतिक बदलाव पर जोर दिया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि पूंजीगत व्यय से भौतिक संपत्तियां और लंबे समय तक उत्पादक क्षमता बनती है, जिससे इसका आर्थिक मल्टीप्लायर प्रभाव (लगभग 2.5 से 4.5) राजस्व व्यय (जो 1 के करीब होता है) की तुलना में बहुत अधिक होता है।

108. उत्तर: (a)

व्याख्या:

कथन 1 सही है; आठ कोर उद्योगों (कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली) का 'औद्योगिक उत्पादन सूचकांक' (IIP) में शामिल वस्तुओं के कुल वेटेज में लगभग 40.27% हिस्सा है। कथन 2 गलत है क्योंकि कोर उद्योगों में रिफाइनरी उत्पादों का व्यक्तिगत वेटेज सबसे अधिक है, उसके बाद बिजली और स्टील का स्थान आता है।

109. उत्तर: (b)

व्याख्या:

भारत विदेशी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा घर भेजे जाने वाले भारी वित्तीय प्रवाह के कारण भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। यह पूंजी प्रवाह भारत के 'चालू खाता संतुलन' (Current Account Balance) के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है।

110. उत्तर: (c)

व्याख्या:

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार के मामले में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। यह अक्सर चीन के साथ शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन USA के साथ व्यापार अधिशेष (trade surplus) होने के कारण भारत को एक विशेष लाभ मिलता है।

111. Answer: (b)

Explanation:

Following structural disruptions from external global shocks, the Central Government laid down a revised fiscal consolidation glide path aiming to systematically bring down the fiscal deficit to below 4.5% of GDP.

112. Answer: (c)

Explanation:

Due to heavy domestic demand and limited home reserves, India imports over 80% of its crude oil requirements. Consequently, Petroleum, Oil, and Lubricants (POL) consistently remains the largest individual element in India's merchandise import bill.

113. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct; the fiscal deficit in BE 2026-27 is estimated to be 4.3% of GDP, aligning with the new fiscal prudence path. Statement 2 is incorrect because the debt-to-GDP ratio is estimated to decline to 55.6% of GDP in BE 2026-27 from 56.1% in RE 2025-26, gradually freeing up resources.

114. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct; the Finance Minister announced that the new Income-tax Act, 2025, will come into effect from April 2026 to simplify tax compliance. Statement 2 is incorrect because the new Act replaces the older framework entirely to reduce multiplicity and ease administration rather than running parallelly.

115. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct. To support the IT sector as a growth engine, the budget clubbed software development, IT-enabled services, knowledge process outsourcing (KPO), and related contract R&D under one unified category. Furthermore, to boost ease of doing business, the safe harbour threshold was significantly raised from ₹300 crore to ₹2,000 crore via an automated rule-driven process.

111. उत्तर: (b)

व्याख्या:

बाहरी ग्लोबल झटकों से संरचनात्मक रुकावटों के बाद, केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को व्यवस्थित रूप से GDP के 4.5% से नीचे लाने के लक्ष्य के साथ एक संशोधित राजकोषीय समेकन मार्ग (fiscal consolidation glide path) तय किया।

112. उत्तर: (c)

व्याख्या:

भारी घरेलू मांग और सीमित घरेलू भंडार के कारण, भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 80% से अधिक आयात करता है। नतीजतन, पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (POL) लगातार भारत के मर्चेंडाइज आयात बिल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत घटक बना हुआ है।

113. उत्तर: (a)

व्याख्या:

कथन 1 सही है; BE 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% अनुमानित है, जो नए राजकोषीय विवेक मार्ग के अनुरूप है। कथन 2 गलत है क्योंकि ऋण-से-GDP अनुपात के RE 2025-26 में 56.1% से घटकर BE 2026-27 में GDP का 55.6% होने का अनुमान है, जिससे धीरे-धीरे संसाधन मुक्त होंगे।

114. जवाब: (a)

स्पष्टीकरण:

बयान 1 सही है; वित्त मंत्री ने घोषणा की कि टैक्स से जुड़े नियमों का पालन आसान बनाने के लिए नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बयान 2 गलत है क्योंकि नया एक्ट पुराने ढांचे की जगह पूरी तरह से ले लेगा, न कि उसके साथ-साथ चलेगा; इसका मकसद कई तरह की जटिलताओं को कम करना और प्रशासन को आसान बनाना है।

115. जवाब: (c)

स्पष्टीकरण:

दोनों बयान सही हैं। IT सेक्टर को ग्रोथ इंजन के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, बजट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT-इनेबल्ड सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (KPO) और संबंधित कॉन्ट्रैक्ट R&D को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा, 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिए, एक ऑटोमेटेड नियम-आधारित प्रक्रिया के ज़रिए 'सेफ़ हार्बर' की सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है।

116. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct; the budget integrated assessment and penalty proceedings into a common order to simplify compliance. Statement 2 is incorrect because the quantum of pre-payment was actually reduced from 20% to 10%, calculated strictly on the core tax demand, lowering the financial burden on taxpayers during disputes.

117. Answer: (b)

Explanation:

As mentioned by the Union Finance Minister in her Budget speech, the Union Budget 2026-27 holds historical significance as it is the first budget prepared in Kartavya Bhawan.

118. Answer: (b)

Explanation:

According to the Revised Estimates of 2025-26, out of the total estimated expenditure of 49.6 lakh crore, the capital expenditure component accounts for about 11 lakh crore.

119. Answer: (b)

Explanation:

To address the practical compliance issues of small taxpayers like relocated NRIs, students, and tech professionals, the Union Budget 2026-27 introduced a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for assets/income below a specified threshold size.

120. Answer: (b)

Explanation:

The Union Budget 2026-27 extended the existing tax deductions available to primary cooperative societies (initially for milk, oilseeds, fruits, or vegetables) to now include the supply of cattle feed and cotton seed produced by their members.

121. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct because the fiscal deficit for 2026-27 is targeted at 3% of GSDP (Rs 1.18 lakh crore). Statement 2 is incorrect because the state does not estimate a revenue deficit; instead, it estimates a revenue surplus of 1.6% of GSDP (Rs 64,458 crore) for 2026-27.

116. उत्तर: (a)

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है; बजट ने अनुपालन को आसान बनाने के लिए असेसमेंट और पेनल्टी की कार्यवाही को एक ही आदेश में मिला दिया। कथन 2 गलत है क्योंकि प्री-पेमेंट की मात्रा असल में 20% से घटाकर 10% कर दी गई थी, जिसकी गणना मुख्य टैक्स मांग के आधार पर की गई थी, जिससे विवादों के दौरान टैक्सपेयर्स पर वित्तीय बोझ कम हो गया।

117. उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है।

118. उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण:

2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, 49.6 लाख करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय में से, पूंजीगत व्यय का हिस्सा लगभग 11 लाख करोड़ रुपये है।

119. उत्तर: (b)

व्याख्या:

दूसरे देशों में बसे NRI, छात्रों और टेक पेशेवरों जैसे छोटे करदाताओं की व्यावहारिक अनुपालन समस्याओं को हल करने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में एक निश्चित सीमा से कम मूल्य की संपत्ति/आय के लिए 6 महीने की एक बार की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू की गई।

120. उत्तर: (b)

व्याख्या:

केंद्रीय बजट 2026-27 ने प्राथमिक सहकारी समितियों (शुरू में दूध, तिलहन, फल या सब्जियों के लिए) को मिलने वाली मौजूदा कर कटौती का दायरा बढ़ाकर अब उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु आहार और कपास के बीज की आपूर्ति को भी इसमें शामिल कर लिया है।

121. उत्तर: (a)

व्याख्या:

कथन 1 सही है क्योंकि 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का 3% (1.18 लाख करोड़ रुपये) रखा गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य ने राजस्व घाटे का अनुमान नहीं लगाया है; इसके बजाय, इसमें 2026-27 के लिए GSDP के 1.6% (64,458 करोड़) के रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान लगाया गया है।

122. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct based on the economic data provided for 2024-25. The state's GSDP at constant prices is estimated to grow by 9.0% (surpassing India's estimated GDP growth of 6.5%), and the services sector leads the economy with a 47% contribution.

123. Answer: (b)

Explanation:

Statement 1 is incorrect because the state expects to raise 50% (Rs 3,61,245 crore) of its revenue receipts through its own resources, while the remaining 50% will come from the Centre. Statement 2 is correct because State GST is projected to be the single largest source of own tax revenue, holding a 45% share.

124. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct because the 16th Finance Commission has allocated a 17.62% individual share to Uttar Pradesh in the divisible pool. Statement 2 is incorrect because the 16th Finance Commission has actually discontinued revenue deficit grants, sector-specific grants, and state-specific grants that were previously recommended by the 15th Finance Commission.

125. Answer: (b)

Explanation:

The Finance Minister of Uttar Pradesh, Mr. Suresh Kumar Khanna, presented the state budget for the financial year 2026-27 on February 11, 2026.

126. Answer: (d)

Explanation:

The GSDP of Uttar Pradesh for 2026-27 at current prices is projected to be Rs 39.8 lakh crore, which represents a 28% growth over the revised estimates of 2025-26.

127. Answer: (b)

Explanation:

To promote micro, small, and medium enterprises, the state government announced the "Sardar Vallabh Bhai Patel Employment and Industrial Zone" scheme with an initial allocation of Rs 575 crore.

122. उत्तर: (c)

व्याख्या:

2024-25 के लिए दिए गए आर्थिक आंकड़ों के आधार पर दोनों बयान सही हैं। स्थिर कीमतों पर राज्य की GSDP में 9.0% की वृद्धि का अनुमान है (जो भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.5% से अधिक है), और सर्विस सेक्टर 47% योगदान के साथ अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है।

123. उत्तर: (b)

व्याख्या:

बयान 1 गलत है क्योंकि राज्य को अपनी रेवेन्यू रिसीट्स का 50% (₹3,61,245 करोड़) अपने संसाधनों से जुटाने की उम्मीद है, जबकि बाकी 50% केंद्र से आएगा। कथन 2 सही है क्योंकि राज्य GST के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है, जिसकी हिस्सेदारी 45% है।

124. उत्तर: (a)

व्याख्या:

कथन 1 सही है क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने बंटवारे योग्य पूल में उत्तर प्रदेश के लिए 17.62% हिस्सा तय किया है। कथन 2 गलत है क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने वास्तव में राजस्व घाटा अनुदान, सेक्टर-स्पेसिफिक अनुदान और राज्य-विशिष्ट अनुदानों को बंद कर दिया है, जिनकी सिफारिश पहले 15वें वित्त आयोग ने की थी।

125. उत्तर: (b)

व्याख्या:

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया।

126. उत्तर: (d)

व्याख्या:

मौजूदा कीमतों पर 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का GSDP ₹39.8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 28% की वृद्धि दर्शाता है।

127. उत्तर: (b)

व्याख्या:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने ₹575 करोड़ के शुरुआती आवंटन के साथ "सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र" योजना की घोषणा की।

RACE IAS General Studies

RACE IAS Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS General Studies

RACE IAS Rajesh Academy for Civil Examinations

128. Answer: (b)

Explanation:

The 16th Finance Commission recommended that Lucknow and Kanpur will be eligible for a special infrastructure grant of up to Rs 5,000 crore each for the development of wastewater management systems.

129. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct according to the historic first Economic Survey of Uttar Pradesh (2025-26). The state's GSDP recorded a CAGR of 10.8% over the specified nine-year span, and the targeted output size for FY 2025-26 stands at ₹36 lakh crore, aiming toward a \$1 trillion economy roadmap.

130. Answer: (b)

Explanation:

Statement 1 is incorrect because Agriculture (25.8%) and Industry (27.2%) are closely aligned, but neither dominates the overall composition. Statement 2 is correct as the Service sector is the largest economic driver, holding a dominant 47% share.

131. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct. The Economic Survey marks Uttar Pradesh as a leading player in the primary sector, contributing 20.6% to India's total foodgrain output and contributing 15.66% to national milk production.

132. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct. The public debt-to-GSDP ratio dropped from 29.3% in 2016-17 to a more disciplined 28.0% in 2024-25. Meanwhile, revenue generation surged, with own tax revenues jumping 2.5 times to 2.09 lakh crore.

128. उत्तर: (b)

व्याख्या:

16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि लखनऊ और कानपुर अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियों के विकास के लिए प्रत्येक को 5,000 करोड़ तक के विशेष बुनियादी ढांचा अनुदान के लिए पात्र होंगे।

129. उत्तर: (c)

व्याख्या:

उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पहले आर्थिक सर्वेक्षण (2025-26) के अनुसार दोनों कथन सही हैं। राज्य की GSDP ने बताई गई नौ साल की अवधि में 10.8% की CAGR दर्ज की, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लक्षित आउटपुट का आकार ₹36 लाख करोड़ है, जिसका लक्ष्य \$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रोडमैप है।

130. उत्तर: (b)

व्याख्या:

कथन 1 गलत है क्योंकि कृषि (25.8%) और उद्योग (27.2%) के आँकड़े काफी करीब हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कुल संरचना पर हावी नहीं है। कथन 2 सही है क्योंकि सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा आर्थिक चालक है, जिसकी हिस्सेदारी 47% है।

131. उत्तर: (c)

स्पष्टीकरण:

दोनों कथन सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश को प्राथमिक क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में बताता है, जो भारत के कुल अनाज उत्पादन में 20.6% और राष्ट्रीय दूध उत्पादन में 15.66% का योगदान देता है।

132. उत्तर: (c)

स्पष्टीकरण:

दोनों कथन सही हैं। सार्वजनिक ऋण-से-GSDP अनुपात 2016-17 में 29.3% से घटकर 2024-25 में 28.0% हो गया। इस बीच, राजस्व सृजन में तेज़ी आई, और अपना कर राजस्व 2.5 गुना बढ़कर 2.09 लाख करोड़ हो गया।

133. Answer: (c)

Explanation:

The State Finance Minister Suresh Kumar Khanna presented the first-ever Economic Survey of Uttar Pradesh 2025-26 in the state legislature on February 9, 2026, creating a data-driven blueprint for policy tracking.

134. Answer: (c)

Explanation:

While per capita income successfully doubled from 54,564 (2016-17) to ₹1,09,844 in 2024-25, the structural growth target for the immediate fiscal year 2025-26 was explicitly mapped out to reach 1,20,000.

135. Answer: (b)

Explanation:

The state government's core model for industrial progress and attracting ₹50 lakh crore in proposals relies on the "Triple S" framework, which stands for Safety (improving law & order), Stability (policy certainty), and Speed (fast clearance via digital ecosystems like Nivesh Mitra).

136. Answer: (a)

Explanation:

While Uttar Pradesh climbed to the 4th position in the overall national Export Preparedness Index 2024, it successfully captured the 1st Rank when explicitly classified among India's landlocked states.

137. Answer: (c)

Explanation:

Both statements are correct. NITI Aayog launched the SDG India Index to track the progress of all States and UTs on social, economic, and environmental parameters. In successive editions, Kerala has consistently been one of the top-performing states due to its robust healthcare and education outcomes.

133. उत्तर: (c)

व्याख्या:

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 9 फरवरी, 2026 को राज्य विधानसभा में उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया, जिससे नीति की निगरानी के लिए डेटा-आधारित ब्लूप्रिंट तैयार हुआ।

134. उत्तर: (c)

व्याख्या:

जबकि प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 54,564 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,09,844 रुपये हो गई (यानी दोगुनी हो गई), वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संरचनात्मक विकास का लक्ष्य स्पष्ट रूप से 1,20,000 रुपये तक पहुंचने का रखा गया था।

135. उत्तर: (b)

व्याख्या:

औद्योगिक प्रगति और 50 लाख करोड़ के प्रस्तावों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार का मुख्य मॉडल "ट्रिपल S" फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसका अर्थ है सेफ्टी (कानून-व्यवस्था में सुधार), स्टेबिलिटी (पॉलिसी में निश्चितता) और स्पीड (निवेश मित्र जैसे डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से तेज़ी से मंजूरी)।

136. उत्तर: (a)

व्याख्या:

जबकि उत्तर प्रदेश समग्र राष्ट्रीय एक्सपोर्ट प्रिपेयर्नेस इंडेक्स 2024 में चौथे स्थान पर पहुंच गया, भारत के लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में इसने सफलतापूर्वक पहली रैंक हासिल की।

137. उत्तर: (c)

व्याख्या:

दोनों कथन सही हैं। नीति आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पैमानों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया। लगातार कई संस्करणों में, केरल अपने मज़बूत स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा परिणामों के कारण लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है।

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

138. Answer: (b)

Explanation:

The Wholesale Price Index (WPI) tracks changes in the price of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses. It is published monthly by the Office of the Economic Adviser under the Ministry of Commerce and Industry.

139. Answer: (a)

Explanation:

Statement 1 is correct because the IBC offers a time-bound process to resolve bad loans and corporate distress efficiently. Statement 2 is incorrect because the National Company Law Tribunal (NCLT) handles cases for companies and limited liability partnerships (LLPs), whereas the Debt Recovery Tribunal (DRT) handles individuals and partnership firms.

140. Answer: (b)

Explanation:

Statement 1 is incorrect because Corporation Tax is a direct tax levied on the net income of companies; its burden cannot be legally shifted. Statement 2 is correct because GST is a landmark indirect tax collected at the final point of consumption across multiple value-addition stages.

141. Answer: (b)

Explanation:

The Prime Minister served as the ex-officio Chairman of the Planning Commission. Gulzarilal Nanda was appointed as its very first Deputy Chairman in March 1950 to oversee operational economic planning.

142. Answer: (b)

Explanation:

The Balance of Trade (BoT) specifically isolates and measures the difference between the monetary value of a nation's merchandise (visible) exports and merchandise imports.

138. उत्तर: (b)

व्याख्या:

होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) होलसेल बिज़नेस द्वारा थोक में बेचे और ट्रेड किए जाने वाले सामान की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 'ऑफिस ऑफ़ द इकोनॉमिक एडवाइज़र' द्वारा हर महीने पब्लिश किया जाता है।

139. उत्तर: (a)

व्याख्या:

बयान 1 सही है क्योंकि IBC खराब लोन और कॉर्पोरेट संकट को कुशलतापूर्वक सुलझाने के लिए एक समय-सीमा वाली प्रक्रिया देता है। बयान 2 गलत है क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs) के मामलों को देखता है, जबकि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) व्यक्तियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामलों को देखता है।

140. उत्तर: (b)

व्याख्या:

बयान 1 गलत है क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनियों की नेट इनकम पर लगाया जाने वाला एक डायरेक्ट टैक्स है; इसका बोझ कानूनी रूप से किसी और पर नहीं डाला जा सकता। कथन 2 सही है क्योंकि GST एक अहम अप्रत्यक्ष कर है, जो कई वैल्यू-एडिशन चरणों से गुजरने के बाद खपत के अंतिम बिंदु पर वसूला जाता है।

141. उत्तर: (b)

व्याख्या:

प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष (ex-officio Chairman) होते थे। गुलजारीलाल नंदा को मार्च 1950 में इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि वे आर्थिक योजना के कामकाज की देखरेख कर सकें।

142. उत्तर: (b)

व्याख्या:

व्यापार संतुलन (BoT) खास तौर पर किसी देश के माल (दृश्य) निर्यात और माल आयात के मौद्रिक मूल्य के बीच के अंतर को अलग करता है और मापता है।

143. Answer: (b)

Explanation:

Statement 1 is incorrect because the LFPR includes both people who are working AND those who are actively looking for work (the entire labor force), not just the employed. Statement 2 is correct because the WPR isolates the segment of the population that is actively employed.

144. Answer: (c)

Explanation:

The Asian Development Bank (ADB) was conceived in the early 1960s and established in December 1966. It is headquartered in Metro Manila, Philippines, and focuses on poverty reduction and regional development.

145. Answer: (b)

Explanation:

According to NCERT macroeconomic principles, Net National Product (NNP) is calculated by deducting the value of wear and tear of capital assets (depreciation) from the Gross National Product (GNP). Thus, $NNP = GNP - \text{Depreciation}$. When evaluated at factor cost, NNP is called National Income.

146. Answer: (c)

Explanation:

Core inflation is a measure of inflation that excludes transitory or volatile items like food and energy products from the Consumer Price Index (CPI). It helps policymakers and central banks understand the baseline, structural price trends driven by demand-supply dynamics without temporary seasonal supply shocks.

147. Answer: (c)

Explanation:

The RBI mandates that all domestic commercial banks (excluding Regional Rural Banks and Small Finance Banks, which have higher targets) must direct 40% of their Adjusted Net Bank Credit (ANBC) or Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher, toward designated priority sectors like agriculture, MSMEs, education, and housing.

143. उत्तर: (b)

व्याख्या:

कथन 1 गलत है क्योंकि LFPR में वे लोग शामिल होते हैं जो काम कर रहे हैं और वे भी जो सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं (पूरी श्रम शक्ति), न कि केवल रोजगार पाए हुए लोग। कथन 2 सही है क्योंकि WPR आबादी के उस हिस्से को अलग करता है जो सक्रिय रूप से रोजगार में है।

144. उत्तर: (c)

व्याख्या:

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की योजना 1960 के दशक की शुरुआत में बनी थी और इसे दिसंबर 1966 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मेट्रो मनीला, फिलीपींस में है और यह गरीबी कम करने और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

145. उत्तर: (b)

व्याख्या:

NCERT के मैक्रोइकॉनॉमिक सिद्धांतों के अनुसार, नेट नेशनल प्रोडक्ट (NNP) की गणना ग्राँस नेशनल प्रोडक्ट (GNP) से कैपिटल एसेट्स (पूँजीगत संपत्तियों) की टूट-फूट (डेप्रिसिएशन) के मूल्य को घटाकर की जाती है। इस प्रकार, $NNP = GNP - \text{डेप्रिसिएशन}$ । जब फैक्टर कॉस्ट (कारक लागत) पर मूल्यांकन किया जाता है, तो NNP को राष्ट्रीय आय (National Income) कहा जाता है।

146. उत्तर: (c)

व्याख्या:

कोर इन्फ्लेशन महंगाई का एक पैमाना है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से भोजन और ऊर्जा उत्पादों जैसी अस्थायी या अस्थिर वस्तुओं को हटा देता है। यह नीति-निर्माताओं और केंद्रीय बैंकों को अस्थायी मौसमी सप्लाई झटकों के बिना मांग-आपूर्ति की गतिशीलता से प्रेरित बुनियादी, संरचनात्मक मूल्य ट्रेड को समझने में मदद करता है।

147. उत्तर: (c)

व्याख्या:

RBI का नियम है कि सभी घरेलू कमर्शियल बैंकों (रीजनल रूरल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को छोड़कर, जिनके लिए लक्ष्य अलग हैं) को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) या ऑफ़-बैलेंस शीट एक्सपोज़र के क्रेडिट इक्विवैलेंट अमाउंट (इनमें से जो भी ज़्यादा हो) का 40% हिस्सा तय प्रायोरिटी सेक्टरों, जैसे कि एग्रीकल्चर, MSME, शिक्षा और हाउसिंग के लिए देना होगा।

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

RACE IAS
General Studies
Rajesh Academy for Civil Examinations

148. Answer: (b)

Explanation:

A Revenue Deficit occurs when the government's consumption or day-to-day operational expenses (revenue expenditure) outpace its regular tax and non-tax earnings (revenue receipts). It indicates that the government is borrowing to fund non-asset-creating consumption operations rather than productive investments.

149. Answer: (c)

Explanation:

The National Development Council (NDC) was established on August 6, 1952, on the recommendation of the First Five Year Plan draft. It was formed to strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of the Plan, and to ensure uniform economic policies across all states.

150. Answer: (c)

Explanation:

India was an original negotiating member of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which includes ASEAN members and their key FTA partners. However, in November 2019, India walked out of the agreement due to unaddressed concerns regarding market access, trade deficits with China, and protection for its domestic dairy and manufacturing sectors.

RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies



RACE IAS General Studies

RACE IAS General Studies



148. उत्तर: (b)

व्याख्या:

रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब सरकार का उपभोग या रोज़मर्रा का ऑपरेशनल खर्च (रेवेन्यू खर्च) उसकी रेगुलर टैक्स और नॉन-टैक्स कमाई (रेवेन्यू रिसीट्स) से ज़्यादा हो जाता है। यह बताता है कि सरकार प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बजाय नॉन-एसेट-क्रिएटिंग उपभोग कार्यों के लिए उधार ले रही है।

149. उत्तर: (c)

व्याख्या:

नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल (NDC) की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को पहली पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट की सिफारिश पर की गई थी। इसे योजना के समर्थन में देश के प्रयासों और संसाधनों को मज़बूत और संगठित करने और सभी राज्यों में एक जैसी आर्थिक नीतियां सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

150. उत्तर: (c)

व्याख्या:

भारत 'रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप' (RCEP) का शुरुआती बातचीत करने वाला सदस्य था, जिसमें ASEAN सदस्य और उनके मुख्य FTA पार्टनर शामिल हैं। हालाँकि, नवंबर 2019 में, भारत इस समझौते से बाहर हो गया क्योंकि मार्केट तक पहुँच, चीन के साथ व्यापार घाटे और अपने घरेलू डेयरी और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के संरक्षण से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं हो पाया था।

